हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

हर खबर पर पैनी नजर

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

वर्ष:4 अंक:241 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये pathpravah.com हरिद्वार, शुक्रवार, 05 सितंबर 2025

▸ 7

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 13 महिलाओं को तीलू रौतेली व 33 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित राज्य स्त्री शक्ति, तीलू रौतेली एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार वितरण समारोह में कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पण और निष्ठा के साथ कार्य करती रहेगी।

कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार और 33 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को उत्कृष्ट सेवा कार्य सम्मान प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने वीरांगना तीलू रौतेली को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने महज 15 वर्ष की आयु में अदम्य साहस और रणकौशल का परिचय दिया, इसलिए उन्हें उत्तराखंड की झांसी की रानी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ÷नारी तू नारायणी÷ मंत्र के साथ मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। चाहे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की पहल हो, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी योजना हो या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत - केंद्र सरकार ने हर स्तर पर महिलाओं को मजबूत किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य सरकार भी महिलाओं के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रही है। सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण, देश में पहली बार समान नागरिक संहिता लागू करना, महिला समूहों को 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण देना और उद्यमिता विकास कार्यक्रम जैसी योजनाएं इसका उदाहरण हैं। वर्ष 2023 से तीलू रौतेली पुरस्कार राशि को 31 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपये और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान 21 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ाया गया है। अब आंगनवाड़ी बहनों को 9300, मिनी आंगनवाड़ी को 6250 और सहायिकाओं को 5250 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइज़र के पद पर पदोन्नति देने का प्रावधान भी किया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद ÷हाउस ऑफ हिमालयाज÷ जैसी पहल से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड के नाम होगा और इसमें महिला समूहों की भूमिका निर्णायक रहेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि हाल की आपदाओं से प्रदेश कठिनाई में है, लेकिन सरकार हर प्रभावित तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और इसमें केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है।

इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। समारोह में विधायक खजान दास, सचिव चंद्रेश कुमार, निदेशक बंशीलाल राणा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं।

पुरस्कार विजेता

अल्मोड़ा - मीता उपाध्याय, बागेश्वर - अलिशा मनराल, चमोली - सुरभि, चम्पावत - अनामिका बिष्ट, देहरादून - शिवानी गुप्ता, हरिद्वार - रूमा देवी, नैनीताल - नैना, पौड़ी गढ़वाल - रोशमा देवी, पिथौरागढ़ - रेखा भट्ट, रुद्रप्रयाग - हेमा नेगी करासी, टिहरी - साक्षी चौहान, ऊधमसिंह नगर - रेखा, उत्तरकाशी - विजयलक्ष्मी जोशी।

GST रिफॉर्म पर क्या बोले पीएम मोदी

कांग्रेस ने तो बच्चों की टॉफी पर लगा दिया था 21% टैक्स

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि जीएसटी सुधार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस फैसले के लागू होने तारीख की घोषणा करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरलीकृत जीएसटी व्यवस्था 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगी। इस दौरान उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाता था। उन्होंने कहा कि बच्चों की टॉफी पर कांग्रेस सरकार 21 फीसदी टैक्स लगाती थी।

पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की सरकार ने कैसे आपका मंथली बजट बढ़ाया हुआ था, यह कोई भूल नहीं सकता। टूथपेस्ट, साबुन, बालों के तेल, इन पर 27% टैक्स। खाने की प्लेट, चम्मच आदि पर 18-28 फीसदी टैक्स लगता था। रोजमर्रा की

हर चीज पर कांग्रेस के जमाने में इतना सारा टैक्स लगता था। हालत यह थी कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। पता नहीं उस समय आप लोगों का अखबार में ध्यान गया होगा, पता नहीं, मोदी ने किया होता तो बाल नोंच लेते। साइकिल पर भी 17 फीसदी टैक्स लगता था। सिलाई मशीन पर 16% टैक्स लगता था। मिडिल क्लास के लिए घूमना-फिरना सब कांग्रेस ने मुश्किल कर दिया गया था।

उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म पर आगे कहा, अगर मैं सार बताऊं तो कह सकता हूं कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। टैक्स सिस्टम सिंपल हुआ, भारत के नागरिक की क्वालिटी लाइफ बढ़ेगी, कंजम्प्शन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्ट मिलेगा। ईज ऑफ ड्यूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा और विकसित भारत के लिए राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस साल जीएसटी में ही कमी नहीं की गई, इनकम टैक्स में भी कमी हुई है। 12 लाख टैक्स तक जीरो किया गया। आजकल आप आईटीआर फाइल किया जा रहा है, तब इस फैसले का सुखद अहसास होता है। यानी कि इनकम में भी बचत और खर्च में भी बचत। अब यह डबल धमाका नहीं है तो क्या है।

उन्होंने कहा, अब जीएसटी और भी आसान हो गया है... 22 सितंबर को, जो नवरात्रि का पहला दिन है, अगली पीढ़ी का सुधार लागू होगा क्योंकि ये सभी चीजें निश्चित रूप से 'मातृशक्ति' से जुड़ी हैं।

गांवों में भी कम बच्चे पैदा करने लगे लोग, हम दो और हमारे दो से नहीं बढ़ रहे आगे

नई दिल्ली। भारत के सिर्फ शहरों में ही नहीं, बल्कि गांवों में भी अब लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। हम दो और हमारे दो की नीति पर चलते हुए गांवों में कुल प्रजनन दर (टोटल फर्टिलिटी रेट- टीएफआर) पहली बार प्रति महिला 2.1 बच्चों के आंकड़े तक गिर गई है। औसतन एक महिला सिर्फ दो बच्चे को ही जन्म दे रही है। यह वह जनसांख्यिकीय सीमा है, जिस पर जन्म दर मृत्यु दर के बराबर होती है, ताकि जनसंख्या का स्तर स्थिर बना रहे। इससे यह भी पता चला कि देश में कुल प्रजनन दर पहली बार 2 से नीचे 1.9 पर आ गई है। 2023 सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) की रिपोर्ट बुधवार को जारी की गई है। इससे यह पता चला है कि देश में मृत्यु दर महामारी से ठीक पहले के स्तर से ऊपर बनी हुई है। गांवों में प्रजनन दर में गिरावट को ऐतिहासिक माना जा रहा है।

भालू के आतंक से ग्रामीणों को शीघ्र मिलेगी निजात: डॉ. धन सिंह रावत

पथ प्रवाह, देहरादून

श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के थलीसैण विकासखंड के कई गांवों में भालू के लगातार हमलों से दहशत का माहौल है। भालू अब तक दो दर्जन से अधिक मवेशियों को निवाला बना चुका है और स्कूली बच्चों व ग्रामीणों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने भालू को आदमखोर घोषित करने और आवश्यक होने पर अंतिम विकल्प के रूप में मार गिराने के निर्देश जारी किए हैं।

आज यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर मंत्री डॉ. रावत की अध्यक्षता में वन विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें गढ़वाल वन प्रभाग की पैठाणी रेंज के अंतर्गत कुण्डिल, कुचोली, सौंठ, कठयूड़, कुठ और खण्डतल्ला गांवों में भालू के आतंक पर विस्तार से चर्चा हुई। डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, ÷ग्रामीणों और बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जनता भयमुक्त जीवन जी सके, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। बैठक में अपर सचिव वन सी. रवि शंकर, प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) रंजन कुमार मिश्रा, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

निर्णय के मुख्य बिंदु

प्रभावित क्षेत्रों में पहले पिंजरे लगाकर भालू को सुरक्षित पकड़ने का प्रयास होगा। असफल होने पर ट्रैंक्यूलाईज कर पकड़ने की कार्यवाही की जाएगी। यदि सभी प्रयास विफल होते हैं तो ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भालू को नष्ट करने की अनुमति दी गई है।

देहरादून में 'अत्यधिक वर्षा और आपदाएँ' विषय पर हुआ विचार-मंथन

पथ प्रवाह, देहरादून

हिमालय सप्ताह (4-9 सितम्बर) के अवसर पर भाकृअनुप-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान (आईआईएसडब्ल्यूसी), देहरादून में ÷उत्तराखंड में अत्यधिक वर्षा की घटनाएँ और आपदाएँ = प्रभाव, तैयारी और उपाय÷ विषय पर एक विचार-मंथन सत्र आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मभूषण से सम्मानित एवं हेस्को के संस्थापक डॉ. अनिल पी. जोशी रहे। उन्होंने हिमालय की संवेदनशीलता और वहन-क्षमता आधारित विकास की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ. जोशी ने उपभोक्तावादी दृष्टिकोण को बदलकर पारिस्थितिक संतुलन और सतत विकास की दिशा में अग्रसर होने का आह्वान किया।

विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित इं. मनु गौड़ (सदस्य, एसएसी उत्तराखंड) ने कहा कि आपदाओं से बचाव के लिए केवल लक्षणों पर नहीं बल्कि मूल कारणों पर ध्यान देना होगा। वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता एवं शोधकर्ता अनूप नौटियाल ने अनियंत्रित मानवीय हस्तक्षेपों को आपदाओं का मुख्य कारक बताते हुए समुदाय आधारित उपायों पर जोर दिया।

आईआईएसडब्ल्यूसी के निदेशक डॉ. एम. मधु ने बढ़ती अत्यधिक वर्षा और बादल फटने जैसी घटनाओं पर चिंता जताई और एकीकृत प्रबंधन एवं संरक्षण रणनीतियों की आवश्यकता पर बल दिया। आयोजन सचिव डॉ. एम. मुरुगनंदम ने अतिथियों का स्वागत कर कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की।

कार्यक्रम में 110 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों और सरकारी विभागों के वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल थे। प्रमुख संस्थानों में आईआईआरएस, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, जेडएसआई, एनआईआरडीपीआरटीआर गुरुग्राम और भाकृअनुप-वीपीकेएएस अल्मोड़ा शामिल रहे।

चर्चा का मुख्य फोकस अत्यधिक वर्षा और उसकी तीव्रता से खेती, पशुपालन, मत्स्य, वानिकी, अवसंरचना और आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव रहे। प्रतिभागियों ने पूर्व चेतावनी तंत्र को मजबूत बनाने, जनमत को विकास योजनाओं में सम्मिलित करने, लचीले अवसंरचना विकास तथा समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण की सिफारिश की।

कार्यक्रम का संचालन डॉ. मुरुगनंदम एवं उनकी टीम ने किया। इस विचार-मंथन से प्राप्त सुझावों को एक संकलन के रूप में तैयार किया जाएगा, जो नीति-निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए भविष्य की रणनीतियों का मार्गदर्शक बनेगा।

डीएवी पब्लिक स्कूल देहरादून में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया शिक्षक दिवस

पथ प्रवाह, देहरादून। डीएवी पब्लिक स्कूल देहरादून में शिक्षक दिवस पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और वैदिक परंपराओं की छटा के बीच मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और मंत्रोच्चार के बीच दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। दीप प्रज्ज्वलन का कार्य विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिकाओं नीता जोशी, नीरू नवानी, कंचन कंडारी, गुरप्रीत अरोड़ा एवं जगजीत कौर ने प्रधानाचार्या शालिनी समाधिया के सहयोग से संपन्न किया। शिक्षक दिवस के अवसर पर कक्षा 12 के विद्यार्थियों ने विद्यालय का अध्यापन कार्यभार संभालकर अद्भुत अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों को चरण स्पर्श कर बधाई दी और आशीर्वाद प्राप्त किया। विद्यालय प्रांगण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से गूंज उठा। विद्यार्थियों ने समूह गीत और नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियां दीं, जिन्हें देख कर पूरा वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट और संगीत की मधुर ध्वनियों से भर गया। वरिष्ठ अध्यापिका नीरू नवानी ने विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासन और संस्कारों के महत्व से अवगत कराया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं विद्यालय के हेड बॉय कार्तिकेय और हेड गर्ल श्रेया ध्यानी ने भावपूर्ण शब्दों में सभी शिक्षकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्या शालिनी समाधिया ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान का संचार नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और संस्कारों की नींव है। उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों से निरंतर सीखते रहने और भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों को आत्मसात करने का आह्वान किया।

जनता को असुविधा या परेशानी न हो, यह हमारी पहली प्राथमिकता: ऋतु खण्डूडी

एआरटीओ कार्यालय पहुंची विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी ने किया औचक निरीक्षण

पथ प्रवाह संवाददाता। कोटद्वार, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खण्डूडी भूषण ने गुरूवार की सुबह 10ः15 बजे तडियाल चौक स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (ARTO) का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि अफसरों की लापरवाही से जनता का कामकाज प्रभावित नहीं होना चाहिए।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर की जांच की। अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, वाहन फिटनेस जाँच एवं सड़क परिवहन से संबंधित अन्य सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि परिवहन कार्यालय में प्रतिदिन बड़ी संख्या में आम लोग आते हैं। जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा या परेशानी न हो, यह हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुंचें, कार्य में गति और पारदर्शिता लाएं तथा जनता की हर समस्या का त्वरित समाधान करें। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएँ। जनता को अनावश्यक कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। ऑनलाइन माध्यम और मैसेज का उपयोग कर यहां पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जाए। कार्यालय में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। ऋतु खण्डूडी भूषण ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई सामने आती है तो सम्बंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऋतु खण्डूडी भूषण ने कहा कि सरकार और प्रशासन का पहला दायित्व जनता की सुविधा और सेवा है।

एक नजर

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सिंगटाली पुल को दी 57 करोड़ की मंजूरी

पथ प्रवाह, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल-कुमांऊ को जोड़ने वाले सिंगटाली मोटर पुल के निर्माण कार्य को कराने की मंजूरी दे दी है। यमकेश्वर विधायक रेनू बिष्ट और सिंगटाली मोटर पुल संघर्ष समिति ने खुशी जाहिर की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में मुलाकात कर पुल निर्माण के लिए 57 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर आभार जताया। संघर्ष समिति ने कहा कि यह पुल पिछले दो दशकों से लंबित था। स्वीकृति मिलने से अब न केवल क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी, बल्कि गढ़वाल और कुमांऊ के बीच सीधा संपर्क भी सुदृढ़ होगा। समिति ने मुख्यमंत्री से जल्द भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष उदय सिंह नेगी समेत कई सदस्य मौजूद रहे।

पर्वतीय सीमांत क्षेत्र में एयर एम्बुलेंस बनी जीवनदायिनी, गर्भवती महिला को उत्तरकाशी से एम्स ऋषिकेश रेफर

दुर्गम इलाकों में समय पर पहुंची हेली सेवा, परिजनों ने जताया आभार

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह /उत्तरकाशी। पर्वतीय सीमांत क्षेत्रों में जहां सड़क मार्ग बाधित होते रहते हैं और स्वास्थ्य सुविधाएँ भी सीमित हैं, वहां राज्य सरकार की एयर एम्बुलेंस सेवा आमजन के लिए संजीवनी साबित हो रही है। गुरुवार को इसी सेवा की बदौलत उत्तरकाशी की एक गर्भवती महिला की जान बचाई जा सकी। ग्राम उत्तरों निवासी 25 वर्षीय अंजली पत्नी लोकेश मखलोगा की हालत अचानक गंभीर हो गई। प्राथमिक इलाज के बाद जब स्थानीय स्तर पर उनकी स्थिति संभालना मुश्किल हो गया तो जिला प्रशासन ने तत्काल एयर एम्बुलेंस सेवा को सक्रिय किया। कन्सेण जोशियाड़ा हैलीपैड से महिला को हेलीकॉप्टर के माध्यम से आपातकालीन चिकित्सा सहायता हेतु सीधे एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से महिला को समय पर बेहतर इलाज मिल पाया। ग्रामीणों और परिजनों ने कहा कि पर्वतीय सीमांत क्षेत्रों में आए दिन मरीजों को बड़े अस्पतालों तक पहुँचाने में समय की सबसे बड़ी चुनौती होती है।

एक नजर

नगर निगम हरिद्वार की सख्त कार्रवाई, बिना अनुमति लगाए गए डिश व इंटरनेट के तार हटाए

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार, नगर आयुक्त नंदन कुमार के निर्देश पर नगर निगम हरिद्वार ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवमूर्ति चौक से रेलवे स्टेशन तक लगे डिश टीवी और इंटरनेट फाइबर के अवैध तारों को हटाया। नगर निगम की इस कार्रवाई से जहां शहर में सौंदर्यीकरण और स्वच्छता अभियान को गति मिलेगी, वहीं आमजन को भी राहत मिलेगी। अव्यवस्थित रूप से तारों के गुच्छे लटकने से न केवल विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही थी बल्कि दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती थी। नगर निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के केबल, तार या उपकरण पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थलों पर नहीं लगाए जाएंगे। निगम ने केबल ऑपरेटरों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निर्देशित किया है कि वे तुरंत अपने तारों को हटा लें, अन्यथा निगम इन्हें स्वयं हटाएगा और इससे उत्पन्न होने वाली पूरी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी/संस्था की होगी। नगर निगम की इस मुहिम को स्थानीय नागरिकों ने सराहा है और इसे शहर की सुव्यवस्था एवं सुरक्षा की दिशा में अहम कदम बताया है।

एचईसी कॉलेज में शिक्षक दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार, एचईसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स, हरिद्वार में शिक्षक दिवस के अवसर पर क्लचरल क्लब की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संस्थान के चेयरमैन संदीप चौधरी ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिवस भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं महान शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समर्पित है। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्या डॉ. तृप्ति अग्रवाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। क्लचरल क्लब की ओर से कार्यक्रम का निर्देशन रितु मोदी और वैष्णवी झा ने किया, जबकि मंच संचालन कशिश, सोनाक्षी, शिवांग और ऐश्वर्य ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रा वाहिनी द्वारा प्रेरणादायी नृत्य प्रस्तुति से हुई। इसके बाद छात्रों ने ÷शिक्षक की सलाह का महत्व÷ शीर्षक से नाटिका मंचित की, जिसमें कशिश, सोनाक्षी, शिवांग, ऐश्वर्य, अमर, रीती, खुशी, चित्रांश और पुलकित ने भाग लिया। छात्रों ने कॉमिक एक्ट भी प्रस्तुत किया जिसमें अनिष्का, नित्या, अनन्या, हर्षित और नितीश शामिल रहे। कार्यक्रम में छात्राओं ने पारंपरिक नृत्यों की भी शानदार प्रस्तुतियां दीं। इस अवसर पर उमराव सिंह, रश्मि सक्सेना, सुनीति त्यागी, दीपशिखा बोहरा, करूणा नेहरा, डॉ. निधि जोशी, डॉ. तनु चन्द्रा, राजा मनीष, सपना सकलानी, दीपाली अग्रवाल, डॉ. पूजा, गौरव, अकांक्षा सहित सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे।

एसडीआईएमटी में संपन्न हुई एक दिवसीय इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट कार्यशाला

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार, स्वामी दर्शनानंद इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी (एसडीआईएमटी) में गुरुवार को एक दिवसीय इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का संचालन असिस्टेंट प्रोफेसर दिव्या राजपूत ने किया। इस अवसर पर डेमिगोड एग्रो फूड प्रा.लि. की मार्केटिंग एवं प्रोडक्ट डेवलपमेंट हेड साक्षी गुप्ता ने छात्र-छात्राओं को एंटरप्रेन्योरशिप और उसकी महत्वता पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने नए बिजनेस आइडियाज, इनोवेशन और स्टार्टअप्स से जुड़ी संभावनाओं पर प्रकाश डाला तथा विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। संस्थान की निदेशक डॉ. जयलक्ष्मी ने कहा कि आज के दौर में स्किल डेवलपमेंट सफलता की कुंजी है।

झिलमिल झील में सम्पन्न हुआ नेचुरलिस्ट एडवांस प्रशिक्षण, गूज्जर समुदाय की रही अहम भागीदारी

पथ प्रवाह, हरिद्वार

झिलमिल झील में पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड और Tourism & Hospitality Skill Council (THSC) द्वारा आयोजित नेचुरलिस्ट एडवांस प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। इस विशेष प्रशिक्षण में लगभग 80 प्रतिशत प्रतिभागी गूज्जर समुदाय से थे, जिनमें तीन गूज्जर बालिकाओं की सक्रिय भागीदारी ने कार्यक्रम को और खास बना दिया।

कार्यक्रम में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद की अतिरिक्त निदेशक पूनम चन्द और वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी महेश शर्मा मौजूद रहे। प्रशिक्षक तौकीर आलम, जो स्वयं गूज्जर समुदाय से हैं और एक युवा पक्षी विशेषज्ञ व प्रकृति प्रेमी के रूप में जाने जाते हैं, ने प्रशिक्षण को व्यवहारिक और प्रभावी बनाया। समापन अवसर पर पूनम चन्द ने सभी छात्रों को उत्तराखण्ड पर्यटन का मानचित्र भेंट करते हुए राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा, ऐसे प्रशिक्षण युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देंगे। वहीं, महेश शर्मा ने कहा कि गूज्जर समुदाय का प्रकृति और जंगलों से गहरा रिश्ता है। इस तरह की पहल उन्हें अपनी पारंपरिक जानकारी को आधुनिक पर्यटन और संरक्षण से जोड़ने का अवसर देगी। छात्रों ने भी अपने अनुभव साझा किए। यह एडवांस कोर्स था, जिसमें 90 प्रतिशत छात्र पहले ही बेसिक कोर्स कर चुके थे। प्रशिक्षण से उन्हें जैव विविधता की गहरी समझ और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की नई दृष्टि प्राप्त हुई।

गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पाण्डेय ने की विकास कार्यों की समीक्षा

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार, आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में गुरूवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मण्डलीय विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान जिन विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गयी, उनको आयुक्त द्वारा सख्त निर्देश देते हुए अपेक्षित प्रगति लाने के लिए कहा। जिन विभागों एवं अधिकारियों द्वारा विकास कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करने में लापरवाही की जाएगी उनके खिलाफ कार्यवाही की चेतावनी दी गई। समस्त जिला स्तरीय विभागों को मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे द्वारा निर्देश दिये गये कि आयक्त गढ़वाल मंडल की आगामी समीक्षा बैठक तक सभी सम्बन्धित विभाग बीस सूत्रीय कार्यक्रम, जिला योजना सहित अन्य सभी विकास कार्यों की शत प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित की जाये। बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत ष्ठ श्रेणी, ष्ट श्रेणी की मदों में प्रत्येक दशा में, श्रेणी लाना सुनिश्चित किया जाये। जिला योजना के अंतर्गत अवमुक्त धनराशि का शतप्रतिशत व्यय करना सुनिश्चित किया जाये। इसी प्रकार केंद्र पोषित एवं राज्य योजना की धनराशि के व्यय में तेजी लाई जाय तथा गतिमान कार्यों को समयबद्ध तरीके से समयसीमा में पूर्ण किया जाये। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सभी विभागों को यह भी निर्देश दिये गये कि जिला योजना आदि कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 2 तारीख जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय को हार्ड एवं शॉफ्ट कॉपी में प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये। प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करने को सभी विभाग गंभीरता से लेना सुनिश्चित करेंगे। समीक्षा बैठक में जिला विकास अधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला पंचायतीराज अधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, अधिशासी अभियंता, सिंचाई, टयूबवेल, लोक निर्माण विभाग, पेयजल निगम, जल सस्थान, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अपर सांख्यकीय अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी आदि सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मेलाधिकारी ने किया कुम्भ मेला क्षेत्र का निरीक्षण, अधिकारियों को दिये समय से कार्य पूरा करने के निर्देश

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार, मेलाधिकारी सोनिका ने गुरूवार को हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को कार्य समय से शुरू कर उन्हें गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिये। कहा कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। मेला क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान मेलाधिकारी सोनिका ने श्री यंत्र मन्दिर सेतु के पास जिन घाटों पर निर्माण कार्य किया जाना है उसके लिए सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को जल्द कार्य शुरू करने के निर्देश दिये। बैरागी कैप पर हो रहे अतिकम्रण को हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि अतिक्रमण फिर न हो इसकी भी निगरानी की जाए। धनौरी सिडकुल लिंक मोटर मार्ग पर नये पुल के निर्माण के लिए कार्यस्थल का निरीक्षण किया। गंग नहर कांवड पटरी मार्ग के निरीक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त मार्ग को सुधारीकरण के साथ-साथ चौड़ीकरण के निर्देश दिये। सतीकुण्ड के सौन्दयीकरण कार्य करने के निर्देश दिये। श्री यंत्र मन्दिर से लेकर पायलट बाबा आश्रम से होते हुए लक्सर मार्ग का चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। आर्यनगर चौक से बाल्मीकि चौक तक सड़क को देहरादून की राजपुर रोड़ की तरह विकसित करने के लिए कहा। अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग को निर्देश दिये गये हैं कि उनके द्वारा जो भी कार्य किये जाने हैं उन कार्यों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि कुम्भ मेला-2027 को दिव्य एवं भव्य ढंग से आयोजित किया जाए। इस दौरान दयानन्द सरस्वती, अपर मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, हरिद्वार, ओमजी गुप्ता, अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, हरिद्वार, दीपक अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग एवं अतुल, राष्ट्रीय राजमार्ग व संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

दैनिक
पथ प्रवाह
हरिद्वार, शुक्रवार 05 सितंबर 2025

संपादकीय

जीएसटी 2.0 : भारतीय अर्थव्यवस्था और आमजन पर दूरगामी असर

जीएसटी परिषद का हालिया निर्णय भारतीय कर ढांचे में एक ऐतिहासिक सुधार है। परिषद ने 12 और 28 प्रतिशत वाले स्लैब को खत्म कर केवल दो मुख्य दरें - 5 और 18 प्रतिशत - लागू करने का फैसला किया है। वहीं, लग्जरी और 'सिन गुड्स' पर 40 प्रतिशत का विशेष स्लैब रहेगा। यह नई व्यवस्था 22 सितंबर से लागू होगी और इसका असर उपभोक्ताओं से लेकर उद्योग जगत और सरकार के राजस्व तक हर स्तर पर महसूस होगा।

सबसे सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा, खासकर देश के मध्य वर्ग को, जिसकी आबादी करीब 35-40 करोड़ है और जो कुल खपत का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा रखता है। रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे कपड़े, जूते, साबुन, शैम्पू और साइकिल अब सस्ते होंगे। पनीर, रोटी और पराठा जैसी खाने-पीने की चीजें शून्य कर श्रेणी में आ चुकी हैं। स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर कर खत्म कर दिया गया है, जबकि जीवन रक्षक दवाएं भी अब टैक्स से मुक्त होंगी। इससे न केवल मासिक बजट हल्का होगा बल्कि बीमा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी आसान होगी। यह बदलाव ऐसे समय आया है जब भारत में जीवन बीमा कवरेज अभी भी महज 4 प्रतिशत आबादी तक सीमित है।

उद्योग जगत के लिए यह सुधार नई संभावनाएं खोलता है। वस्त्र उद्योग, जो 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है और निर्यात में 11 प्रतिशत योगदान करता है, घटे कर से प्रतिस्पर्धात्मक बनेगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सौर पैनल और उपकरण सस्ते होने से हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो भारत के जीडीपी में 7 प्रतिशत और कुल विनिर्माण में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है, छोटे वाहनों पर टैक्स में कमी से डिमांड में इजाफा देखेगा। इन तीनों क्षेत्रों में रोजगार और उत्पादन की नई लहर उठ सकती है।

सरकार का यह कदम वैश्विक परिदृश्य में भी रणनीतिक महत्व रखता है। अमेरिका ने हाल ही में भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है। इससे निर्यात दबाव में आ सकता है। ऐसे समय में घरेलू मांग को मजबूत करना और आंतरिक खपत को प्रोत्साहित करना भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है। यही वजह है कि जीएसटी सुधार को केवल कर ढांचे का सरलीकरण नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था को वैश्विक दबाव से सुरक्षित करने की कोशिश भी माना जा रहा है।

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि टैक्स दरों में कमी से शुरुआत में राजस्व पर दबाव पड़ सकता है, लेकिन खपत बढ़ने और कर अनुपालन सरल होने से यह घाटा लंबे समय में संतुलित हो जाएगा। कर चोरी की गुंजाइश घटेगी और टैक्स कलेक्शन स्थिर होगा। उद्योग संगठनों का आकलन है कि यह बदलाव कारोबारी माहौल को पारदर्शी बनाएगा और श्वड्डह्यद्ग शद्ध ष्ठश्चद्बठ्ठद्द क्चह्वह्यद्बठ्ठद्गह्यह्य को मजबूती देगा।

जीएसटी सुधार का सामाजिक पहलू भी उल्लेखनीय है। स्वास्थ्य और बीमा को करमुक्त करना एक ऐसी नीति है जो आम नागरिक की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करती है। इससे समाज में आर्थिक असमानता घटेगी और अधिक से अधिक लोग बुनियादी सेवाओं से जुड़ पाएंगे।

कुल मिलाकर, जीएसटी स्लैब में यह बदलाव तीन स्तरों पर असर डालेगा - आम उपभोक्ता को राहत, उद्योगों को अवसर और सरकार को स्थायी राजस्व। यह केवल टैक्स स्लैब का सरलीकरण नहीं, बल्कि विश्वास, पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता का नया अध्याय है, जो भारत की आर्थिक यात्रा को नई ऊर्जा और स्थायित्व प्रदान करेगा।

प्रसंगतः धर्म की भूमिका

काशी के एक संत गंगा किनारे कुटी बना कर रहते थे। एक बार वह प्रवचन करने किसी दूसरे आश्रम में जा रहे थे। रास्ते में एक व्यापारी मिला। संत ने उससे पूछा, 'क्या पीपल बाबा के आश्रम का रास्ता यही है?' व्यापारी बोला, 'हां, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। आप भी मेरे साथ चलिए।' दोनों चलने लगे। व्यापारी ने पूछा, 'आप तो विद्वान संत हैं। एक बात समझ में नहीं आती कि आप जैसे संत के होते हुए भी देश में अराजकता फैली हुई है। कोई धर्म के रास्ते पर चलता ही नहीं। ऐसे धर्म का क्या फायदा कि लोग अपनी बुराई छोड़ते ही नहीं और ऐसे महात्माओं का क्या फायदा जिनके प्रवचनों का असर लोगों पर पड़ता ही नहीं।' संत ने पूछा, 'आप क्या करते हैं?' व्यापारी ने कहा, 'मेरा साबुन बनाने का कारखाना है।' इतने में एक किसान भी आ गया। वह दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। संत ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, 'तुम्हारे कपड़े तो बहुत गंदे हैं। सफाई क्यों नहीं करते?' किसान ने कोई जवाब नहीं दिया। संत ने व्यापारी से कहा, 'ऐसे साबुन बनाने से क्या फायदा कि लोगों के कपड़े अब भी गंदे हैं।' इस पर व्यापारी बोला, 'महात्मा जी, इसमें साबुन का क्या दोष। साफ-सुथरा रहने के लिए लोगों को स्वयं साबुन से कपड़े धोने चाहिए। कुछ लोगों की आदत ही होती है गंदा रहने की।' संत मुस्करा कर बोले, 'तुम ठीक कहते हो। इसी तरह संतों का काम लोगों को अच्छे गुण सिखाना है और धर्म के बारे में लोगों को जागृत करना है। यह काम तो लोगों का है कि वे संतों की वाणी को अपने जीवन में उतारें। मगर कुछ लोगों के अनसुना करने से न तो धर्म का महत्व कम होता है और न ही महात्माओं का। जिस तरह कई लोग साबुन का लाभ उठाते हैं उसी तरह संतों की वाणी का बहुत से लोगों पर गहरा असर पड़ता है।'

धरती की हरियालीः स्थानीय प्रयासों से वैश्विक प्रेरणा की ओर

डॉ अनिता जोशी
पर्यावरण संरक्षण विशेषज्ञ
(जैव विविधता में शोध एवं पी एच डी)

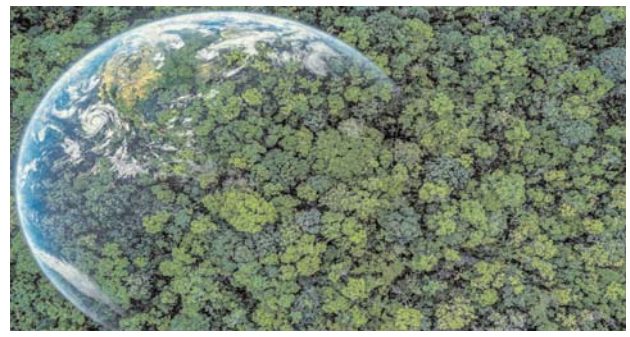

जीवन सिंह बोहरा पिथौरागढ़

पेड़ बचेंगे तो सांसें सुरक्षित होंगी,नदी बहेगी तो धरती पावन होगी

जैव विविधता का संरक्षण ही मानवता का धर्म है

वरना आने वाली पीढ़ी सिर्फ़ विरानगी में खो जाएगी

प्रकृति और पर्यावरण आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे महत्वपूर्ण विमर्श का विषय बन चुके हैं। जलवायु परिवर्तन, वनों की अंधाधुंध कटाई, मिट्टी का कटाव, जल स्रोतों का क्षरण, वन्य जीवों का विस्थापन और प्रदूषण–इन सबने हमारी धरती को संकट के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि यदि अब भी मानवता ने सचेत होकर कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियाँ केवल किताबों और तस्वीरों में ही नदियों की स्वच्छ धारा, जंगलों की हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट देख पाएँगी। यह समस्या किसी एक देश, किसी एक क्षेत्र या किसी एक समाज की नहीं है, बल्कि यह वैश्विक संकट है। इसका समाधान भी केवल सरकारों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। ज़रूरत इस बात की है कि हर गाँव, हर कस्बा, हर समुदाय अपने स्तर पर आगे बढ़कर पर्यावरण संरक्षण को अपना दायित्व बनाए।

इतिहास गवाह है कि दुनिया में बड़े परिवर्तन अक्सर छोटे-छोटे प्रयासों से शुरू हुए हैं। जब अफ्रीका के केन्या में वांगारी मथाई ने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की नींव रखी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह आंदोलन एक दिन वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बनेगा। वर्ष 1977 में शुरू हुआ यह अभियान महिलाओं को संगठित करने और पेड़ लगाने की साधारण सी पहल से शुरू हुआ था। लेकिन धीरे-धीरे यह आंदोलन इतना व्यापक हो गया कि इसने न केवल पांच करोड़ से अधिक पेड़ लगाने में सफलता पाई बल्कि लाखों महिलाओं को आजीविका, सम्मान और नेतृत्व भी प्रदान किया। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट ने दुनिया को यह सिखाया कि पेड़ लगाना केवल हरियाली पैदा करना नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का माध्यम भी है।

यही दर्शन आज भारत के हिमालयी राज्य उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में कार्यरत अभिलाषा समिति ने अपने काम से साकार किया है। समिति ने तीन वर्षों में जो कुछ किया है, वह स्थानीय प्रयासों की शक्ति और सामुदायिक सहयोग की ताकत को सामने लाता है। समिति ने अब तक 51,000 पौधारोपण किए हैं। यह संख्या केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उस जीवंत हरियाली का प्रतीक है जिसे समिति ने धरती की गोद और लोगों के मन दोनों में स्थापित किया है।

इन पौधों में चारा-पत्ती प्रजातियाँ हैं, जो पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था वाले इस क्षेत्र के किसानों के लिए जीवन रेखा का काम कर रही हैं। फलदार प्रजातियाँ हैं, जो पोषण और आजीविका दोनों में सहायक हैं। चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष हैं, जो जल स्रोतों को रिचार्ज कर रहे हैं और भविष्य की प्यास बुझाने का संकल्प लिए हुए हैं।

समिति का बीज पोटली अभियान विशेष उल्लेखनीय है। छोटे-छोटे बीजों को पोटलियों में डालकर जंगलों और बंजर भूमि में फैलाया गया ताकि वे स्वाभाविक रूप से अंकुरित हों और प्रकृति का नया जीवन चक्र शुरू हो। यह पहल केवल तकनीकी नवाचार नहीं है, बल्कि विश्वास और आस्था की मिसाल भी है। इस अभियान ने यह संदेश दिया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े-बड़े प्रोजेक्ट और भारी-भरकम योजनाएँ जरूरी नहीं हैं। छोटे और सामूहिक प्रयास भी असाधारण परिणाम ला सकते हैं।

इस अभियान का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा कि समिति ने बच्चों और विद्यालयों को इसके केंद्र में रखा। विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिताएँ और पेंटिंग प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं, जिनमें बच्चों ने अपने शब्दों और रंगों के माध्यम से उस भविष्य की तस्वीर बनाई जिसमें नदियाँ स्वच्छ हैं, जंगल सुरक्षित हैं और जीव-जंतु निडर होकर विचरण कर रहे हैं। बच्चों ने जब अपने लगाए पौधों को अपना मित्र मानकर उनकी देखभाल शुरू की तो यह केवल वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि यह एक भावनात्मक और जीवन्त संबंध बन गया। यही संवेदनशीलता भविष्य की पर्यावरणीय सुरक्षा की गारंटी है।

यह आंदोलन विद्यालयों और बच्चों तक ही सीमित नहीं रहा। समाज के विभिन्न वर्गों–ग्राम सभाओं, महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और युवाओं–को इसमें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। समिति ने यह सिद्ध कर दिया कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं का विषय नहीं है। यह जनसहभागिता का उत्सव है। जब गाँव का हर बच्चा, हर महिला, हर किसान इसमें शामिल होता है तो संरक्षण केवल नारा नहीं रह जाता, बल्कि जीवन की शैली बन जाता है।

उत्तराखंड के संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है वनाग्नि। हर वर्ष हजारों हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ जाते हैं, जिससे न केवल पर्यावरण को अपार क्षति होती है बल्कि जैव विविधता भी नष्ट होती है। अभिलाषा समिति ने इस त्रासदी को गंभीरता से लिया और ÷वनाग्नि विहिन हिमालय अभियान÷ शुरू किया। रैलियों, गोष्ठियों और जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को यह समझाया गया कि आग बुझाना ही समाधान नहीं है, बल्कि उसे रोकना ही सच्चा उत्तर है। इस अभियान का सबसे प्रभावशाली हिस्सा था हस्ताक्षर आंदोलन, जिसमें हजारों लोगों ने वनाग्नि रोकने की प्रतिज्ञा ली। चारा-पत्ती पौधारोपण और जंगलों में घास की उपलब्धता बढ़ने से आग लगाने की घटनाओं में भी कमी आई है। यह केवल स्थानीय स्तर पर आग पर नियंत्रण का प्रयास नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में योगदान है।

जल संरक्षण पर भी समिति ने व्यापक काम किया। ÷पानी बचाओ आंदोलन÷ के तहत लोगों को याद दिलाया गया कि पानी जीवन का मूल मंत्र है। वर्षा जल संचयन, परंपरागत जल स्रोतों का पुनर्जीवन और नदियों की सफाई जैसे प्रयासों से यह विश्वास जगा कि यदि आज हम सतर्क हुए तो कल का जल संकट टाला जा सकता है।

मानव-वन्य जीव संघर्ष की समस्या को भी समिति ने गंभीरता से लिया। बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधनों के कारण यह संघर्ष लगातार गहराता जा रहा था। समिति ने माधव वन्य जीव संघर्ष निवारण कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें यह समझाया गया कि यह संघर्ष दुश्मनी का परिणाम नहीं, बल्कि संसाधनों की कमी का दुष्परिणाम है। जब जंगलों में भोजन और पानी उपलब्ध होंगे, तो वन्य जीव गाँवों की ओर नहीं आएँगे। इसके लिए चारा-पत्ती पौधारोपण और जल स्रोतों का संरक्षण किया गया। यह सहजीवन का विज्ञान है, जिसने संघर्ष को संवाद में बदलने का मार्ग दिखाया।

इन सब प्रयासों का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव यह रहा कि महिलाओं को जंगलों में चारा लाने के लिए बार-बार नहीं जाना पड़ा। घर के पास ही चारा उपलब्ध होने से उनका समय बचा और इस समय को उन्होंने हस्तशिल्प और अन्य आय आधारित कार्यों में लगाना शुरू किया। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, आत्मनिर्भरता बढ़ी और समाज में उनकी भूमिका मजबूत हुई। पहाड़ों से गिरकर होने वाले हादसे भी कम हुए और साथ ही मानव-वन्य जीव संघर्ष में कमी आई। इस तरह पर्यावरण संरक्षण ने समाज और अर्थव्यवस्था दोनों को नया जीवन दिया।

आज जब हम ग्रीन बेल्ट मूवमेंट और अभिलाषा समिति को एक साथ देखते हैं तो पाते हैं कि इन दोनों के केंद्र में समुदाय की शक्ति है। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट ने अफ्रीका की महिलाओं को सशक्त किया और उन्हें पर्यावरणीय नेतृत्व दिया। अभिलाषा समिति ने उत्तराखंड की महिलाओं, युवाओं और बच्चों को इस जिम्मेदारी से जोड़ा। दोनों ने यह प्रमाणित किया कि पर्यावरण संरक्षण केवल वृक्षारोपण की क्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का औजार है। दोनों ने यह दिखाया कि पेड़ लगाने का अर्थ केवल पर्यावरण सुधारना नहीं है, बल्कि यह आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का मार्ग है।

दुनिया में जब बड़े-बड़े जलवायु सम्मेलन और अंतरराष्ट्रीय समझौते अक्सर धीमी गति से आगे बढ़ते हैं और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी से जूझते हैं, तब स्थानीय स्तर के ये आंदोलन हमें उम्मीद और दिशा देते हैं। यह सिखाते हैं कि वैश्विक संकटों का समाधान केवल उच्च स्तर की नीतियों से नहीं, बल्कि गाँवों और कस्बों से उठने वाली सामुदायिक चेतना से भी हो सकता है। सतत विकास का अर्थ केवल नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं, बल्कि यह स्थानीय भागीदारी और जनसहयोग है।

नीति-निर्माताओं और सरकारों के लिए यह समय है कि वे ऐसे प्रयासों को औपचारिक सहयोग दें। वृक्षारोपण और बीज पोटली अभियानों को सरकारी योजनाओं का हिस्सा बनाया जाए। विद्यालयों में पर्यावरणीय गतिविधियों को व्यवहारिक शिक्षा का अंग बनाया जाए। स्थानीय समुदायों को संरक्षण आधारित उद्यमिता से जोड़ा जाए और अंतरराष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट योजनाओं से ऐसे अभियानों को लाभान्वित किया जाए। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की तरह अभिलाषा समिति के प्रयासों को भी वैश्विक नेटवर्क से जोड़ा जाए, ताकि ये स्थानीय पहलें वैश्विक प्रेरणा बन सकें।

धरती को हरित बनाना केवल पर्यावरणीय लक्ष्य नहीं, बल्कि मानवता के अस्तित्व की अनिवार्यता है। चाहे केन्या हो या उत्तराखंड, चाहे अफ्रीका की धरती हो या हिमालय की गोद, संदेश एक ही है–धरती हमारी साझा धरोहर है और इसे बचाना हमारी साझा जिम्मेदारी। अभिलाषा समिति के लगाए गए 51,000 पौधे केवल पेड़ नहीं हैं, बल्कि जीवन का संकल्प हैं। बीज पोटली केवल बीज नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की पोटली है। विद्यालयों की प्रतियोगिताएँ केवल कार्यक्रम नहीं हैं, बल्कि चेतना की लौ हैं।

ग्रीन बेल्ट मूवमेंट ने अफ्रीका को हरित भविष्य की ओर अग्रसर किया, उसी तरह अभिलाषा समिति हिमालयी गाँवों को आशा, हरियाली और आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। और यही वह संदेश है जिसे अब स्थानीय से वैश्विक स्तर तक गूंजाना होगा। यह केवल उत्तराखंड या भारत की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता का साझा अनुभव है। यदि दुनिया भर के समुदाय ऐसे ही प्रयास करें, तो जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी समस्याओं का हल संभव है।

धरती की रक्षा सरकारों या संस्थाओं का अकेला दायित्व नहीं है। यह हर इंसान, हर समाज और हर समुदाय की जिम्मेदारी है। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट और अभिलाषा समिति ने यह सिखाया है कि यदि समाज और प्रकृति साथ खड़े हों तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह केवल पर्यावरणीय क्रांति नहीं है, बल्कि यह जीवन की पुनर्स्थापना है। यही वह विचार है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी आवश्यकता है–एक हरित भविष्य की ओर बढ़ता हुआ सामूहिक संकल्प।

अभिलाषा समिति के निदेशक डॉ. किशोर कुमार पंत और उनकी टीम से मिलकर, धरातलीय स्तर पर जाकर समझकर तैयार किया गया यह सम्पादकीय ।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की घोषणा, प्रत्येक जनपद में एक-एक वृद्धाश्रम

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित संवाद कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों से मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में एक-एक वृद्धाश्रम की स्थापना की जाएगी, ताकि बुजुर्गों को सम्मान और देखभाल मिल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने की घोषणा की। साथ ही कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा समाप्त कर दी।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया तथा समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की पांचवीं किश्त का ऑनलाइन भुगतान भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। राज्य में 96 हजार से अधिक दिव्यांगजन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। वहीं लगभग 6 लाख बुजुर्गों को डीबीटी के माध्यम से पेंशन सीधे बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जानकारी दी कि वर्तमान में बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी में राजकीय वृद्धाश्रम संचालित हैं, जबकि देहरादून, अल्मोड़ा और चम्पावत में भवन निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल समेत कई जिलों में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम के तहत बुजुर्ग अपने बच्चों या उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण की कानूनी मांग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने वरिष्ठजनों को आश्वस्त किया कि उनकी सुरक्षा, सम्मान और सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजानदास, सविता कपूर, मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।

रेशम कीट बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना उत्तराखंडः कृषि मंत्री गणेश जोशी

पथ प्रवाह, देहरादून

उत्तराखंड ने रेशम उत्पादन के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को जानकारी दी कि राज्य अब रेशम कीट बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है और अन्य राज्यों को भी आपूर्ति करने की क्षमता रखता है।

मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि बीते वर्ष राज्य में 312 मीट्रिक टन शहतूत कोया, 55,352 ओकटसर कोया और 10 हजार किलोग्राम एरी रेशम कोया का उत्पादन किया गया। इससे करीब 9 हजार कृषक परिवार लाभान्वित हुए।

उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण से लेकर अब तक कीटबीज उत्पादन के लिए विभाग केंद्रीय रेशम बोर्ड पर निर्भर था, जिस पर भारी धनराशि खर्च करनी पड़ती थी। लेकिन बसंत फसल में 7 लाख डीएफएल्स का उत्पादन कर उत्तराखंड ने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है।

रेशम क्लस्टर और रोजगार के अवसर

मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उनके निर्देश पर विभाग द्वारा 13.91 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्रीय रेशम बोर्ड को भेजा गया था। इसके अंतर्गत शहतूत और वन्या रेशम क्लस्टरों की स्थापना को मंजूरी मिल चुकी है। अभी तक एक शहतूती और एक वन्या क्लस्टर के लिए 3 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हो गया है। शेष चार क्लस्टरों के लिए जल्द ही धनराशि उपलब्ध होगी। इन क्लस्टरों से 450 परिवारों को रोजगार और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

महिला सशक्तिकरण और प्रशिक्षण

ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना के तहत पिछले वर्ष 13 जनपदों में 300 महिला लाभार्थियों का चयन कर 90 हजार शहतूती पौधों का रोपण किया गया। इन महिलाओं को ककून क्राफ्ट और रेशम धागाकरण का प्रशिक्षण देकर उत्पादन से जोड़ा जा रहा है।

पौड़ी में रेशम कीटपालन का विस्तार

जनपद पौड़ी के यमकेश्वर विकासखंड में देवभूमि रेशम किसान संगठन ने 300 एकड़ भूमि पर शहतूत वृक्षारोपण किया है, जिससे 600 किसान रेशम कीटपालन से जुड़े हैं। भविष्य में यहां धागाकरण और वस्त्र उत्पादन कार्य भी प्रस्तावित है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा।

रेशमी साड़ियों का उत्पादन और नया 'रेशम घर'

उत्तराखंड को-ऑपरेटिव रेशम फेडरेशन के अंतर्गत सेलाकुई स्थित ग्रोथ सेंटर में तीन पावरलूम स्थापित कर प्रदेश में रेशमी साड़ियों का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। वर्ष 2024-25 में 45 हजार मीटर वस्त्र का उत्पादन किया गया। आगामी वर्ष 2025-26 में देहरादून में 'रेशम घर' की स्थापना और सितम्बर माह में सिल्क एक्सपो आयोजित करने की योजना है।

स्वास्थ्य विभाग में 220 नये चिकित्सक तैनात : डॉ. धन सिंह रावत

पथ प्रवाह, देहरादून

राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 220 नये चिकित्सकों की तैनाती कर दी है। इनमें अधिकांश चिकित्सकों को पर्वतीय व दूरस्थ क्षेत्रों की चिकित्सा इकाइयों में नियुक्त किया गया है, जहां लंबे समय से पद रिक्त चल रहे थे।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं अंतिम गांव तक उपलब्ध हों। इसी कड़ी में नवनियुक्त चिकित्सकों को चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और अल्मोड़ा जनपदों की सुदूर चिकित्सा इकाइयों में भेजा गया है। इनमें देवाल, जोशीमठ, गंगोत्री, जानकीचट्टी, बड़कोट, थल, धारचूला, कपकोट, भिकियासैंण, मुक्तेश्वर जैसे क्षेत्र प्रमुख हैं। डॉ धन सिंह रावत ने कहा, ÷सुदूरवर्ती क्षेत्रों में चिकित्सकों की तैनाती से स्थानीय लोगों को नजदीक ही बेहतर उपचार मिलेगा। सरकार का संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी नागरिक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा से वंचित न रहे।

उत्तराखंड के स्कूलों में 240 दिन चलेंगी कक्षाएं, परीक्षा के लिये अलग से समय

पथ प्रवाह, देहरादून। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा को राज्य स्तरीय टास्क फोर्स ने हरी झंडी दे दी है। इसके तहत प्रदेशभर के विद्यालयों में अब 240 दिन अनिवार्य रूप से कक्षाएं संचालित होंगी। साथ ही 20 दिन परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य के लिए और 10-10 दिन सहशैक्षणिक गतिविधियों व बस्ता रहित दिवसों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

सचिवालय सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने की। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने नयी पाठ्यचर्या की रूपरेखा का पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया, जिसे मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, सचिव शिक्षा रविनाथ रमन सहित अन्य सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया।

डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि एनईपी-2020 के अंतर्गत 297 कार्य बिंदु तय किए गए हैं, जिनमें से 202 कार्य राज्य स्तर पर लागू किए जाने हैं। राज्य पाठ्यचर्या की संरचना को पांच भागों में विभाजित किया गया है–

1– उद्देश्य व लक्ष्य - शिक्षा के व्यापक लक्ष्यों, मूल्यों और कौशलों की स्पष्टता।

2– क्रॉस विषय - मूल्य आधारित शिक्षा, पर्यावरणीय संवेदनशीलता, समावेशी शिक्षा व शैक्षणिक प्रौद्योगिकी।

3– विषयवार मानक - विषयवस्तु चयन, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के स्पष्ट दिशा-निर्देश।

4– विद्यालयी संस्कृति - गतिविधियों, पर्यावरणीय वातावरण और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा।

5– शिक्षा तंत्र - सेवा-शर्तें, आधारभूत ढांचा, समुदाय व परिवार की भूमिका।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई पाठ्यचर्या के तहत सप्ताह में 32 घंटे का शैक्षणिक समय निर्धारित किया गया है। सहशैक्षणिक गतिविधियों और बस्ता रहित दिवसों से बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा।

बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, सचिव संस्कृति युगल किशोर पंत, अपर सचिव मनुज गोयल, निदेशक एससीईआरटी वंदना गर्ब्याल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तरकाशी में विधिक जागरूकता शिविर, विद्यार्थियों को दिलाई नशा मुक्ति और यातायात नियमों की शपथ

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और जिला जज व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी के निर्देश पर गुरुवार को ऐंजल एकेडमी मातली में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सचिन कुमार ने छात्र-छात्राओं और उपस्थित आमजन को नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन योजना 2015) के तहत नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं और मादक पदार्थों का सेवन शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। इसके दुष्प्रभाव से खाँसी, गले और फेफड़ों की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही नशे की लत व्यक्ति को अपराध की ओर भी धकेलती है। कई बार नशे के कारण लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, जिससे पूरा परिवार प्रभावित होता है। सचिन कुमार ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है ताकि समाज को नशे से बचाया जा सके। शिविर में उपस्थित विद्यार्थियों और आमजन को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। सचिव सचिन कुमार ने यह भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति नशे की चपेट में है तो उसे जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी लाया जा सकता है, जहाँ मनोचिकित्सक और अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक उसकी मदद के लिए उपलब्ध हैं।

तंबाकू और सिगरेट का सेवन करने वाले भी चिकित्सालय से स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त कर इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। शिविर में यातायात नियमों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। कहा गया कि दुपहिया वाहन चलाते समय चालक और पीछे बैठने वाले को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। चौपहिया वाहन में सभी यात्रियों को सीट बेल्ट लगाना चाहिए। वाहन चलाते समय आर.सी., बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र और वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। 16 वर्ष की आयु पर अस्थायी और 18 वर्ष की आयु पर स्थायी लाइसेंस जारी किया जाता है। यदि वाहन चालक के पास कागज न हों, नाबालिग गाड़ी चलाए, तेज गति से वाहन चलाया जाए, प्रैशर हॉर्न का प्रयोग किया जाए या नशे की हालत में वाहन चलाया जाए तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, जिसमें कारावास और जुर्माना दोनों शामिल हैं। सचिव ने शिविर में मानव तस्करी और अनैतिक तस्करी के दुष्प्रभावों पर भी जानकारी दी। इसके साथ ही मानव तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) अधिनियम 2021 के प्रावधानों के बारे में बताया गया। देहरादून और हल्द्वानी नैनीताल में कार्यरत वाणिज्यिक न्यायालयों की भूमिका और उनके लाभों को भी विस्तार से समझाया गया। इस शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के साथ विद्यालय के शिक्षक, रिटेनर अधिवक्ता, कर्मचारी और पराविधिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

एडीएम मुक्ता मिश्र ने गंगोत्री-यमुनोत्री हाईवे का स्थलीय निरीक्षण किया, ग्रामीणों से सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। चारधाम यात्रा मार्ग पर लगातार हो रही बरसात और आपदा के प्रभावों के बीच बृहस्पतिवार को अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र ने गंगोत्री एवं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर वहां की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने धरासू बैंड से लेकर रानाचट्टी तक के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का गहन निरीक्षण किया और मौके पर चल रहे मरम्मत व सुरक्षा कार्यों की समीक्षा की। अपर जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान रानाचट्टी और स्यानाचट्टी में स्थानीय ग्रामीणों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना। ग्रामीणों ने सड़क अवरोध, जल निकासी व्यवस्था, यातायात बाधा, संचार व्यवस्था और यमुना नदी के कटाव जैसी चुनौतियों से अवगत कराया। इस पर एडीएम ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

उन्होंने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे सभी कार्यों को प्राथमिकता एवं तत्परता से पूरा किया जाए ताकि स्थानीय लोगों और यात्रियों को असुविधा न हो। विशेष रूप से उन्होंने स्यानाचट्टी में यमुना नदी में किए जा रहे चैनलाइजेशन कार्यों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को तकनीकी रूप से सुदृढ़, सुरक्षित और समयबद्ध ढंग से कार्य संपन्न कराने के निर्देश दिए। एडीएम मिश्र ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान मार्गों की सुरक्षा और सुगमता प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कहीं भी कार्य में लापरवाही या देरी पाई गई तो संबंधित विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। निरीक्षण के दौरान एसडीएम बृजेश तिवारी, तहसीलदार रेनू सैनी, मास्टर ट्रेनर मस्तान भंडारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सरकार और जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि आपदा की चुनौतियों के बीच चारधाम यात्रा व स्थानीय जनजीवन सुचारु रूप से चलता रहे।

हर्षिल बाजार में पुलिस की दबिश, 46 अध्धे अंग्रेजी शराब और 16,690 नकदी के साथ 2 व्यक्ति पकड़े गए

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में हर्षिल पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने हर्षिल बाजार क्षेत्र में दो व्यक्तियों को अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियों के साथ गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से नकदी भी बरामद हुई है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत थानाध्यक्ष हर्षिल दीपक रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुधवार 03 सितंबर 2025 को हर्षिल बाजार क्षेत्र में चैकिंग अभियान चलाया। इस दौरान हिमालय फास्ट फूड की दुकान के पीछे से पुलिस ने नेपाल निवासी महेंद्र तांमग और आईसि तांमग को गिरफ्तार किया। तलाशी में दोनों के पास से 46 अध्धे अवैध अंग्रेजी शराब सोलमेट ब्लू और शराब बेचकर अर्जित 16,690 की नकदी बरामद की गई। पुलिस ने गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर दोनों व्यक्तियों के खिलाफ थाना हर्षिल पर 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

1. महेंद्र तांमग पुत्र विष्णु तांमग, निवासी काफलसोर थाना विधुर, जिला नूउकोटा, आंचल बागमती नेपाल (वर्तमान पता - हिमालय फास्ट फूड हर्षिल), उम्र 32 वर्ष।
2. आईसि तांमग पुत्र इंद्र बहादुर तांमग, निवासी कल्याणपुर थाना विधुर, जिला नूउकोटा नेपाल (वर्तमान पता - उपरोक्त), उम्र 34 वर्ष।

बरामद माल - 46 अध्धे अवैध अंग्रेजी शराब (सोलमेट ब्लू) व ?16,690 की नकदी।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. हे0कानि0 अरविंद कुमार
2. कांस्टेबल सुरेंद्र रावत
3. कांस्टेबल कुलदीप तोमर

एक नजर

आंगनवाड़ी कार्यकत्री सरोजनी देवी को मिला उत्कृष्ट सेवा सम्मान

संदीप बर्तवाल, चमोली। पोखरी विकासखंड के गुडम गांव में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकत्री सरोजनी देवी को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं और योगदान के लिए सम्मानित किया गया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं की देखभाल में अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं तभी सफल हो सकती हैं, जब आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करें। सरोजनी देवी की सेवाओं की सराहना करते हुए मंत्री ने उन्हें बधाई दी और कहा कि उनकी लगन और सेवाभाव अन्य कार्यकत्रियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं।

मातृ स्वास्थ्य में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सरकार की बड़ी उपलब्धि

मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) में 12.5% की कमी, मुख्यमंत्री धामी ने जताई प्रसन्नता

राज्य ने मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है। भारत में मातृ मृत्यु पर विशेष बुलेटिन के अनुसार, उत्तराखण्ड का मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) 2020-22 में 104 से घटकर 2021-23 में 91 पर आ गया है। विगत वर्षों में 13 अंकों की कमी और मातृ मृत्यु में 12.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर कहा कि यह राज्य सरकार की समर्पित नीतियों, स्वास्थ्यकर्मियों के अथक प्रयासों और सामुदायिक सहभागिता का परिणाम है। उन्होंने मातृ स्वास्थ्य को और मजबूत बनाने के लिए सतत प्रयास जारी रखने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर डॉ. आर. राजेश कुमार, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन ने कहा मातृ स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह उपलब्धि हमारे समर्पित स्वास्थ्यकर्मियों, सरकारी संस्थानों और सामुदायिक भागीदारों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। हमारा दृढ़ संकल्प है कि मातृ मृत्यु दर को और कम किया जाए तथा प्रत्येक गर्भवती महिला को सुरक्षित और सम्मानजनक प्रसव सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।

मुख्य पहल एवं हस्तक्षेप

मातृ मृत्यु निगरानी एवं प्रतिक्रिया (MDSR): प्रत्येक मातृ मृत्यु की समयबद्ध सूचना और गहन विश्लेषण के आधार पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई। जन्म-तैयारी एवं जटिलता प्रबंधन (BPCR): गर्भवती महिलाओं व परिवारों में जोखिम-चिन्हों की शीघ्र पहचान और आपात स्थितियों में तत्परता।

गुणवत्ता सुधार: लक्ष्य-प्रमाणित प्रसव कक्ष और मातृत्व OT के विस्तार से सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक सेवाएँ। संस्थान-आधारित प्रसव को प्रोत्साहन: JSY और JSSK के सुदृढ़ क्रियान्वयन से निःशुल्क और समावेशी मातृ एवं नवजात सेवाएँ। आपातकालीन परिवहन व्यवस्था: 108/102 एम्बुलेंस सेवाओं का सशक्तीकरण और GPS आधारित रेफरल प्रोटोकॉल। पल्स एनीमिया मेगा अभियान: 57,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं की हीमोग्लोबिन जाँच और स्थिति-विशिष्ट उपचार; दूसरे चरण में सामुदायिक स्तर पर व्यापक स्क्रीनिंग। सामुदायिक सहभागिता: आशा, एएनएम और सीएचओ के नेटवर्क से अंतिम छोर तक ANC/PNC सेवाओं की उपलब्धता। स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने कहा यह उपलब्धि राज्य सरकार की मातृ स्वास्थ्य के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है। राज्य का लक्ष्य है कि कोई भी माँ रोके जा सकने वाले कारणों से जीवन न खोए और उत्तराखण्ड सुरक्षित मातृत्व का आदर्श राज्य बने।

भारत में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या 30 जून, 2025 तक 1 अरब के पार

नई दिल्ली (ईएमएस)। ब्रॉडबैंड ग्रोथ के कारण भारत में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या 30 जून, 2025 तक 1 अरब को पार कर 1,002.85 मिलियन हो गई, जो मार्च की तुलना में 3.48 प्रतिशत अधिक है। यह जानकारी सरकार की ओर से दी गई। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन 100 करोड़ से अधिक ग्राहकों में से 4.47 करोड़ के पास वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन थे, जबकि 95.81 करोड़ के पास वायरलेस कनेक्शन थे। ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की संख्या 3.77 प्रतिशत बढ़कर 979.71 मिलियन हो गई, जबकि नैरोबैंड यूजर्स की संख्या घटकर 23.14 मिलियन रह गई ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की संख्या 3.77 प्रतिशत बढ़कर 979.71 मिलियन हो गई, जबकि नैरोबैंड यूजर्स की संख्या घटकर 23.14 मिलियन रह गई। जून तिमाही में कुल टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 1,218.36 मिलियन तक पहुंच गई, जो पिछली तिमाही की तुलना में 1.46 प्रतिशत अधिक है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार के अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जनपद में मानकों के अनुरूप संचालित न हो रहे क्लीनिकों और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर शिकंजा कसा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए गए सघन चेकिंग अभियान में अनियमितताएँ सामने आने के बाद अल्ट्रा साउंड सेंटरों और हॉस्पिटलों पर बड़ी कार्रवाई की है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर. के. सिंह ने बताया कि शिकायतों के निराकरण और निरीक्षण के लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमेश कुंवर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस टीम में जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी रवि संदल, राजन ठाकुर और कुलदीप बिष्ट शामिल रहे। चेकिंग अभियान के दौरान दो अल्ट्रासाउंड मशीनें मानक अनुसार संचालित न होने पर सील की गई। इसके अलावा तीन अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर मौके पर डॉक्टर न मिलने पर जुर्माना लगाया गया। 19 नैदानिक संस्थानों में नियमावली के उल्लंघन पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया। निरीक्षण के दौरान 9 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।

जिन संस्थानों पर कार्रवाई हुई उनमें मान्य डायग्नोस्टिक (बहादराबाद), ग्लोबल मल्टीस्पेशलिटी, लंढौरा को सील किया गया। दीप अल्ट्रासाउंड (सुल्तानपुर), यशलोक हॉस्पिटल (रुड़की), आर्यावर्त हॉस्पिटल (कनखल) पर जुर्माना लगाया और नोटिस जारी किया गया। नियम उल्लंघन पर लोटस हॉस्पिटल (ज्वालापुर), एसएन पैथोलॉजी लैब (बहादराबाद), मेडविन अस्पताल (रुड़की), दून पैथोलॉजी लैब (लंढौरा), खुशी हॉस्पिटल (लंढौरा), लाइफ हेल्थ केयर (भगवानपुर चंदनपुर), सहारा हॉस्पिटल (मंगलौर), ग्रीन हॉस्पिटल (मंगलौर), डिवाइन हॉस्पिटल (मंगलौर), सिटी हॉस्पिटल (मंगलौर), न्यू मिशन हॉस्पिटल (मंगलौर), फैमिली हेल्थ केयर (सुल्तानपुर), वेलनेस हॉस्पिटल (इमलीखेड़ा), शिखर हॉस्पिटल (इमलीखेड़ा) पर 50–50 हजार का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा चौहान एक्सरे क्लीनिक (लंढौरा), बालाजी एक्सरे सेंटर (लंढौरा), सहारा हॉस्पिटल (सुल्तानपुर), खुशी हेल्थ केयर (भगवानपुर), लाइफलाइन अस्पताल (इमलीखेड़ा) की मशीनें जब्त की गई। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा है कि जनपद वासियों और श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के बाद अब ऐसे संस्थानों पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

एक नजर

राशन की आड़ में पशु तस्करी का प्रयास, मंगलौर पुलिस ने तीन आरोपी दबोचे

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार, एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर चलाए जा रहे अलर्ट बॉर्डर चेकिंग अभियान के तहत गुरुवार सुबह मंगलौर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने राशन की आड़ में दो भैंसवंशीय पशुओं की तस्करी का प्रयास विफल करते हुए तीन आरोपितों को हिरासत में लिया है। प्रातः करीब चार बजे नारसन बॉर्डर पर चौकी प्रभारी हेमदत्त भारद्वाज की टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक छोटे हाथी वाहन (क्रा5श्वज्ञ-4710) को रोका। वाहन चालक और उसके साथियों ने बताया कि वे कलियर उर्स मेले के लंगर के लिए राशन ले जा रहे हैं। संदेह होने पर जब वाहन की तलाशी ली गई तो राशन की बोरियों और फट्टों के नीचे दबे हुए दो कटड़े (भैंसवंशीय पशु) दयनीय स्थिति में मिले। पुलिस ने तुरंत पशुओं को वाहन से निकालकर चारा-पानी उपलब्ध कराया। पुलिस ने मौके से चालक वसीम पुत्र यामीन, कादिर उर्फ भोला पुत्र हसीन और इनायत पुत्र अब्दुल सलाम निवासी मुजफ्फरनगर को हिरासत में लेकर वाहन सीज कर दिया। उनके खिलाफ नियमानुसार मुकदमा दर्ज किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के अपमान पर हरिद्वार में FIR दर्ज करने की मांग

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार, दरभंगा (बिहार) के सिंघवारा-सिमरी क्षेत्र में कांग्रेस और राजद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता श्रीमती हीराबेन मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने का मामला तूल पकड़ गया है। इस घटना को लेकर हरिद्वार के अधिवक्ता अरुण भदौरिया एडवोकेट ने एसएसपी परमिंदर डोभाल को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा और नौशाद के खिलाफ अभियोग दर्ज करने की मांग की है। अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि 31 अगस्त 2025 को फेसबुक और यूट्यूब पर वायरल वीडियो में दरभंगा में आयोजित कांग्रेस-राजद के संयुक्त मंच से स्वर्गीय हीराबेन मोदी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी मौजूद बताए गए। भदौरिया एडवोकेट का कहना है कि इस तरह की अभद्र टिप्पणी न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत गरिमा का अपमान है, बल्कि पूरे देश की जनता की भावनाओं को आहत करती है। उन्होंने कहा कि भारत में मां को देवी का दर्जा दिया जाता है और किसी भी मां का अपमान पूरे समाज का अपमान है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लागू की गई योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत योजना, तीन तलाक पर कानून, धारा 370 हटाना, राम मंदिर निर्माण, जनधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा और मुद्रा लोन योजना का उल्लेख करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि मोदी जी ने सदैव देशहित में कार्य किया है, ऐसे में उनकी माता के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग अस्वीकार्य है।

ज्वालापुर पुलिस ने सीनियर सिटीजनों संग गोष्ठी कर दी साइबर अपराधों की जानकारी

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार, कोतवाली ज्वालापुर पुलिस द्वारा क्षेत्र के सम्मानित सीनियर सिटिजन, पुलिस पेंशनर और विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त नागरिकों के साथ गुरुवार को गोष्ठी का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में बढ़ते साइबर अपराधों – जैसे डिजिटल अरेस्टिंग, साइबर किडनैपिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी के तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देशानुसार थानाध्यक्षों को सीनियर सिटीजनों से नियमित संवाद स्थापित कर उनकी कुशलक्षेम पूछने और समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा गया है।

गोष्ठी के दौरान पुलिस अधिकारियों ने सभी वरिष्ठ नागरिकों से अपने घरेलू नौकरों का सत्यापन कराने की अपील की। साथ ही नशे के दुष्प्रभाव और उसकी रोकथाम पर जानकारी दी गई। यातायात व्यवस्था, ध्वनि प्रदूषण और आसपास रहने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की गोपनीय सूचना पुलिस को देने का आग्रह भी किया गया। सीनियर सिटीजनों को प्रभारी निरीक्षक ज्वालापुर, चौकी प्रभारियों और चेतक पुलिसकर्मियों के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए गए। साथ ही आश्वासन दिया गया कि हर सप्ताह चेतक पुलिसकर्मी उनके घर जाकर कुशलक्षेम पूछेंगे और किसी भी समस्या का त्वरित समाधान करेंगे।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज का सम्माननीय वर्ग हैं। उनकी सुरक्षा और सुविधा हमारी प्राथमिकता है।

बढ़ते साइबर अपराधों से बचाव के लिए समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सीनियर सिटिजन खुद को सुरक्षित और पुलिस के करीब महसूस करें। किसी भी समस्या पर वे बेझिझक हमें या चेतक पुलिसकर्मियों को सीधे जानकारी दें, पुलिस उनकी हर संभव मदद करेगी। उपस्थित सीनियर सिटीजनों ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रयास उन्हें सुरक्षा और विश्वास का एहसास कराता है।

दून पुलिस का सख्त रुख, सड़क हादसों पर लगाम - चालानी कार्रवाई में 50% की बढ़ोतरी

नवीन चौहान

आपका जीवन अनमोल है - इसी संदेश के साथ दून पुलिस सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर लगातार सघन अभियान चला रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के परिणामस्वरूप इस वर्ष सड़क हादसों में कमी दर्ज की गई है। यातायात नियम तोड़ने वालों पर दून पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। वर्ष 2025 के शुरुआती आठ माह में विगत वर्ष की तुलना में चालानी कार्रवाई में 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। खासतौर पर ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है–जहां वर्ष 2024 में 908 मामले सामने आए थे, वहीं इस वर्ष अब तक 3787 मामले दर्ज हुए, जो 336% की वृद्धि है। इसी तरह खतरनाक ड्राइविंग,

ओवरस्पीडिंग और रेड लाइट जम्पिंग पर भी कार्रवाई दोगुनी रही। आंकड़ों के अनुसार–

खतरनाक तरीके से वाहन चलाना : 814 (2024) से बढ़कर 1948 (2025) ओवर स्पीड : 9017 (2024) से बढ़कर 22843 (2025)

रेड लाइट जम्प : 17720 (2024) से बढ़कर 31052 (2025)

अन्य उल्लंघनों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बिना हेलमेट, नाबालिग चालक, तीन सवारी और मोबाइल फोन के प्रयोग जैसे मामलों में पुलिस ने व्यापक कार्रवाई की।

कुल मिलाकर, वर्ष 2024 में 88,025 चालान काटे गए थे, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 1,25,544 तक पहुँच गई।

पुलिस ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहन चालकों और पर्यटकों से भी सहयोग की अपील की है। साथ ही युवा वर्ग और आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और गोष्ठियों का सहारा लिया जा रहा है।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक सम्पन्न

जीवन सिंह बोहरा पिथौरागढ़

आज जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी तथा सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ शिक्षा व्यवस्था से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई एवं आगामी कार्ययोजना निर्धारित की गई। जिलाधिकारी ने बैठक में आपदा

से प्रभावित विद्यालय परिसंपत्तियों का विस्तृत आकलन करने के निर्देश दिए गए। सभी विकासखंडों से तीन दिवस के भीतर फोटो एवं जीपीएस लोकेशन सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। क्लस्टर विद्यालयों की संभावनाओं एवं उनकी विजिबिलिटी पर चर्चा की गई।

इस विषय पर पुनर्विचार कर विस्तृत रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। 10 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों की सूची तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने को कहा गया। लगातार घट रही छात्र संख्या के कारणों पर विस्तार से चर्चा की गई।

प्रोफेसर डॉ हेमलता ही बनी रहेगी कार्यवाहक कुलपति, कर्मचारियों में खुशी की लहर

पथ प्रवाह संवाददाता। गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय में चल रहे प्रशासनिक विवाद पर माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश जारी कर आंदोलनरत कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। माननीय उच्च न्यायालय ने कुलपति प्रोफेसर हेमलता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें नियमित कुलपति की नियुक्ति तक कार्यवाहक कुलपति के रूप में कार्य करने का आदेश दिया है। कर्मचारियों ने अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे भारतीय न्याय प्रणाली और सच्चाई की जीत करार दिया। कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष रजनीश भारद्वाज और महामंत्री नरेंद्र मलिक ने बताया कि आंदोलनरत कर्मचारी पिछले 60 दिनों से धरने पर बैठे थे। यह जीत सभी कर्मचारियों की एकजुटता का परिणाम है। उन्होंने इसे अन्याय के खिलाफ संघर्ष की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। प्रोफेसर हेमलता ने बताया

कि वह उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शुक्रवार को कुलपति कार्यालय में बैठकर कामकाज करेंगी। उन्होंने कहा कि वह हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी रही है। माननीय हाईकोर्ट का निर्णय सच की जीत है। वहीं दूसरी ओर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की जानकारी मिलते ही गुरूकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय परिसर हरिद्वार व कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून में कर्मचारियों ने ढोल-नगाड़े बजाकर जुलूस निकाला और मिठाइयाँ बाँटकर खुशी जताई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राहुल चौधरी, संजीव बाबा, जाट सभा के पदाधिकारी, गुरुकुल विद्यालय विभाग के मुख्याधिष्ठाता डॉ. दीनानाथ शर्मा, शिक्षक संघ पदाधिकारी आदि ने धरना स्थल पर पहुंच कर कर्मचारियों को बधाई दी। बताते चले कि गुरूकुल कांगड़ी में बीते दो माह से कई घटनाक्रम हुए। आर्य प्रतिनिधि सभाओं की ओर से कुलाधिपति के पद पर डॉ एसके आर्य की नियुक्ति हुई। एसके आर्य के पत्र से कार्यवाहक कुलपति के तौर पर डॉ प्रभात कुमार की नियुक्ति हुई। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में कार्यवाहक कुलपति प्रभात कुमार ने कार्यभार संभाला। दो कुलपति और दो रजिस्ट्रार गुरूकुल प्रांगण में रहे। लेकिन गुरूकुल कांगड़ी में प्रशासनिक कार्य बाधित रहा। दो माह में दो बार बीओएम की बैठक हुई। बीओएम के निर्णय भी चर्चाओं में रहे।

यूजीसी की ओर से नियुक्त कुलपति प्रोफेसर हेमलता अंग्रेजी विभाग में बैठकर कार्य करती रही और उन्होंने माननीय हाईकोर्ट से न्याय की गुहार लगाई।

मनेरी पुलिस टीम ने वरिष्ठ नागरिकों को दी साइबर अपराध से बचाव की जानकारी, व्यापारियों को भी किया सचेत

ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। समाज में बढ़ते साइबर अपराधों से लोगों को सुरक्षित रखने और डिजिटल ठगी से बचाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के निर्देशन में कोतवाली मनेरी पुलिस की टीम ने विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया। प्रभारी निरीक्षक मनोज असवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुरुवार 4 सितम्बर 2025 को भटवाड़ी, नेताला और गंगोरी क्षेत्रों का दौरा कर वहां के वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात की और उनकी कुशलक्षेम

जानी। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को साइबर अपराधों की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। टीम ने वरिष्ठ नागरिकों को बताया कि आजकल डिजिटल अरेस्ट, फिसिंग ई-मेल फ्रॉड, ऑनलाइन नौकरी या लॉटरी का झांसा, केवाईसी अपडेटिंग के नाम पर ठगी, निवेश योजनाओं का लालच जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इनसे बचने के लिए किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या लिंक पर भरोसा न करने की हिदायत दी गई। साथ ही यह भी समझाया गया कि यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाए तो बिना समय गँवाए तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या निकटतम थाने में शिकायत दर्ज कराए। पुलिस टीम ने व्यापारियों से भी संवाद किया। इस दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों और अन्य दुकानदारों को चेताया गया कि एसिड और नशीली दवाओं की अवैध बिक्री बिल्कुल न करें, अन्यथा कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एक नजर

देहरादून में 19 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर प्रशासन की छापेमारी, नमक के सैंपल जांच को भेजे

पथ प्रवाह, देहरादून। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर घटिया गुणवत्ता वाले नमक वितरण की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर बुधवार को जनपद की विभिन्न तहसीलों–सदर, चकराता, विकासनगर, मसूरी, डोईवाला और ऋषिकेश–में एक साथ 19 राशन दुकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान उप जिलाधिकारी और तहसीलदारों की संयुक्त टीमों ने दुकानों से नमक के नमूने एकत्रित किए। जिलाधिकारी के आदेश के बाद अपर जिला अधिकारी (प्रशासन) के समन्वय में यह कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नमूनों की जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस टीम से मिला पारिवारिक स्नेह, मुस्कुराए ग्रामीण चेहरे

पिथौरागढ़ पुलिस रख रही है बुजुर्गों का खास ख्याल

जीवन सिंह बोहरा पिथौरागढ़। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ रेखा यादव के निर्देशन में, जनपद पुलिस द्वारा मित्रता, सेवा और सुरक्षा के संकल्प के साथ वरिष्ठ नागरिकों की कुशलक्षेम जानने एवं उनकी समस्याओं के समाधान हेतु एक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस टीमों ने विभिन्न दूरस्थ गाँवों का भ्रमण कर बुजुर्गों से आत्मीय भेंट की। उनकी निजी, पारिवारिक, स्वास्थ्य संबंधी एवं अन्य समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना गया तथा कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। पुलिस टीम ने बुजुर्गों को पुलिस सहायता नंबर 112 एवं मोबाइल नंबर 9411112982 की जानकारी देते हुए आश्वस्त किया कि किसी भी आपात स्थिति में वे बिना झिझक पुलिस से संपर्क करें। पुलिस सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहेगी और उनकी सुरक्षा की गारंटी बनेगी। पुलिस टीम के आत्मीय और मित्रवत व्यवहार से प्रभावित होकर बुजुर्गों की आँखें नम हो उठीं। उन्होंने पुलिस को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि पिथौरागढ़ पुलिस उनके लिए परिवार जैसी है। यह जनहितकारी अभियान निरंतर जारी रहेगा और पिथौरागढ़ पुलिस मित्रता, सेवा और सुरक्षा के वचन के साथ हर पल वरिष्ठ नागरिकों के साथ खड़ी रहेगी।

प्रधानमंत्री जनमन योजना की समीक्षा बैठक सम्पन्न

जीवन सिंह बोहरा पिथौरागढ़

आज विकास भवन सभागार में परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास आशीष पुनेठा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जनमन योजना (PM-JANMAN) की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेन्द्र पाण्डेय ने विभिन्न विभागों में चल रही कार्यों के बारे में जानकारी दी। संबन्धित विभाग के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। परियोजना निदेशक ने विभागवार जानकारी प्राप्त करते हुए अब तक की उपलब्धियों, लंबित कार्यों एवं आने वाली चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की।

प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को समय पर आवास उपलब्ध कराने की स्थिति की समीक्षा की गई। जिन लाभार्थियों को प्रथम व द्वितीय किस्त प्राप्त हो चुकी है, उनके भवन निर्माण की प्रगति जानी गई। परियोजना निदेशक ने अपूर्ण भवनों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण की अद्यतन स्थिति पर चर्चा हुई। खराब मौसम से प्रभावित कार्यों को तेजी से पूर्ण करने हेतु विभाग को

ठोस कार्ययोजना बनाने को कहा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की गई। खराब/निष्क्रिय पेयजल योजनाओं को पुनर्जीवित करने एवं सभी घरों तक जल पहुंचाने पर बल दिया गया।

दूरस्थ व सीमांत क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन किया गया। आशा कार्यकर्त्रियों की सक्रियता तथा दवाइयों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

विद्यालयों में नामांकन की स्थिति, भवन मरम्मत एवं आपदा प्रभावित परिसंपत्तियों के आकलन पर चर्चा की गई। किसानों को उपलब्ध कराई जा रही योजनाओं व लाभों की समीक्षा की गई। आधुनिक तकनीक, बीज व उर्वरक वितरण तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए।

परियोजना निदेशक ने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना का उद्देश्य समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को मुख्यधारा में जोड़ना है और जनपद की राजी जनजाति के लोगों को समाज के अन्य वर्गों से जोड़ना राज्य सरकार और जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसलिए सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रह सके।

बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी अमरेन्द्र चौधरी, मुख्य शिक्षा अधिकारी हरक राम कोहली सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

हरिद्वार रियल एस्टेट में नई जान फूँकेंगे जीएसटी सुधार, घर खरीदना हुआ आसान

नवीन चौहान, हरिद्वार

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 56वीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित सुधारों को मंजूरी मिलने के बाद हरिद्वार का रियल एस्टेट कारोबार नई ऊर्जा से भर गया है। सीमेंट और मार्बल पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% तथा ग्रेनाइट ब्लॉक्स पर 12% से घटाकर 5% करने के फैसले को कारोबारियों और जनप्रतिनिधियों ने ऐतिहासिक कदम बताया है।

जनता को बड़ी राहत – जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान

जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान ने कहा, ÷प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को कर सुधारों के जरिए बड़ी राहत दी है। निर्माण सामग्री पर कर कम होने से आम आदमी के लिए घर बनाना आसान होगा। यह कदम हरिद्वार जैसे तीर्थ और पर्यटन नगरी के विकास को भी नई गति देगा।÷

नई प्रोजेक्ट्स को मिलेगी रफ्तार" - RW कुंज प्रोजेक्ट

RW कुंज प्रोजेक्ट के संचालक सचिन बेनीवाल ने कहा, ÷पिछले कुछ समय से निर्माण लागत लगातार बढ़ रही थी, जिससे प्रॉपर्टी की कीमतों पर दबाव बना हुआ था। अब जीएसटी दरों में कमी से खरीदारों का विश्वास बढ़ेगा और हरिद्वार में नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग तेज होगी।

आर्थिक वृद्धि की राह मजबूत – डॉ. विशाल गर्ग

वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. विशाल गर्ग ने कहा, ÷प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी सुधार देश की आर्थिक वृद्धि को नई दिशा देंगे। हरिद्वार जैसे उभरते शहरों में रियल एस्टेट कारोबार को बल मिलेगा और युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह कदम केवल कारोबारियों के लिए ही नहीं बल्कि आम नागरिकों के लिए भी लाभकारी है।

विशेषज्ञों की राय: कीमतों में स्थिरता की उम्मीद

स्थानीय बिल्डर्स और रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों से हरिद्वार में चल रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को राहत मिलेगी। बढ़ती मांग को देखते हुए प्रॉपर्टी निवेशक और होमबायर्स दोनों को फायदा होगा। निर्माण लागत घटने से फ्लैट्स और प्लॉट्स की कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद है।

हरिद्वार बनेगा निवेश का बड़ा केंद्र

विशेषज्ञों के अनुसार, तीर्थ और पर्यटन के साथ-साथ निवेश का गढ़ बनते हरिद्वार में इन सुधारों का असर और गहरा होगा। आने वाले महीनों में रियल एस्टेट कारोबार को नई उड़ान मिलेगी और आम जनता के लिए घर खरीदना ज्यादा आसान होगा।

स्वामी/प्रकाशक **वीरेन्द्र सिंह** ने मुद्रक **प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)** से मुद्रित कराकर, **मुख्य कार्यालय: 41, शांतिपुरम, जगजीपुर, कनखल, हरिद्वार पिन–249408 (उत्तराखण्ड)** से प्रकाशित किया। **वीरेन्द्र सिंह** (सम्पादक) 9411111733, **सुरेन्द्र पाल सिंह** (ब्यूरो चीफ, उत्तरकाशी) 7376757899 वेबसाई– www.pathpravah.com